THE HINDU

Date: 14-11-25

Urgent update

India needs to revise its Consumer Price Index urgently

Editorial

The retail inflation data for October once again underscore the fact that the update of the Consumer Price Index (CPI) cannot happen fast enough. The data show that the rate of overall inflation fell to just 0.25%, the lowest it has been since at least January 2012. On the face of it, this would be cause for celebration, but a deeper look reveals this drastic fall to be a statistical anomaly rather than an actual fall in price levels. The food and beverages category saw prices falling 3.7% in October, the largest in the history of the CPI's current series. However, the main reason for this contraction was not so much that food prices have fallen, but because food inflation in October last year was a blistering 9.7%. This high base ensured that food inflation in October 2025 was negative, even though vegetable prices in markets have been on the rise recently. With the food and beverages category enjoying a weightage of nearly 46% in the overall CPI basket, this statistical anomaly in food inflation was responsible for pulling the entire index down. Indeed, inflation in nearly every other major sub-group — fuel and light, housing, tobacco, and the miscellaneous category — was higher this October than last. The impact of the GST rate cuts has, so far, been seen only in the clothing and footwear category — the only one apart from food to see inflation lower than last year. All of this shows just how skewed the inflation measure is. Not only is it outdated, with the base year set as 2012, but the weightages are no longer accurate and more often obscure rather than clarify. The disconnect between the CPI and reality can perhaps best be shown by the fact that people the Reserve Bank of India (RBI) had surveyed in September had said that their perceived inflation rate was 7.4% — a far cry from what the CPI reported.

The urgency behind the update is not just because of the vast gap between measured and perceived inflation. It is also because the RBI's Monetary Policy Committee uses the CPI as its benchmark when deciding what to do with interest rates. Its next meeting is in December and it will have to decide whether to keep rates unchanged or to cut them. It will have to contend with growth data clouded by the temporary impact of the GST rate cut-related demand boost. Having to also parse through inflation data beset by statistical anomalies will only make accurate policymaking that much harder. The Ministry of Statistics and Programme Implementation has said that the new series of the CPI will be ready by the first quarter of the next financial year. The sooner it happens, the better.

दैनिक जागरण

Date: 14-11-25

आतंक की गहरी जड़ें

संपादकीय

दिल्ली में लाल किले के निकट कार में विस्फोट के बाद इस आतंकी घटना को लेकर जैसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे यही सिद्ध होता है कि फरीदाबाद आतंकी माड्यूल ने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। इस माड्यूल में शामिल एक डाक्टर की कार में किसी गफलत में विस्फोट होने से आतंकी साजिश का भंडाफोड़ तो हो गया, पर इसकी अनदेखी न की जाए कि वे 26/ 11 जैसी आतंकी घटना को अंजाम देने की ताक में थे।

उन्होंने एक साथ कई धमाके करने के लिए कारें जुटाने के साथ घातक हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा जमा कर लिया था। इस आतंकी साजिश में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ने के साथ फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका को लेकर संदेह गहराने से यही स्पष्ट होता है कि कश्मीर से लेकर देश के अन्य हिस्सों में आतंक की जड़ें कहीं अधिक गहराई तक जम चुकी हैं।

अल फलाह यूनिवर्सिटी केवल इसीलिए कठघरे में नहीं कि वह अप्रत्याशित रूप से बड़ी संख्या में कश्मीरी डाक्टरों को नियुक्त कर रही थी, बल्कि इसलिए भी है कि उसने ऐसे डाक्टरों को भी नौकरी दी, जो दूसरी जगहों से बर्खास्त किए गए थे।

इनमें से एक कश्मीरी डाक्टर को तो आतंक और अलगाववाद की खुली तरफदारी करने के लिए बर्खास्त किया गया था। इसका मतलब है कि अल फलाह प्रबंधन किसी की नियुक्ति के पहले उसकी पृष्ठभूमि जांचने का काम या तो करता ही नहीं था या फिर उसकी अनदेखी करना पसंद करता था। इसे देखते हुए इस शिक्षा संस्थान की गहन जांच जरूरी हो जाती है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य एजेंसियों को फरीदाबाद आतंकी माड्यूल की जांच करते हुए उन कारणों की भी तह तक जाना होगा, जिनके चलते मजहबी उन्माद से ग्रस्त होकर आतंक की राह पर चलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब आतंक के रास्ते पर कोई भी चलता मिल सकता है, वह चाहे अनपढ़ हो या उच्च शिक्षित, निर्धन हो या धनवान।

तथ्य यह भी है कि कट्टर मजहबी तत्वों के जहरीले बयान मात्र किसी को आतंकी नहीं बनाते। इसके साथ उनका अपना परिवेश और खासकर ऐसा विषाक्त नैरिटव भी उन्हें आतंक के रास्ते पर ले जाने का काम करता है कि उन्हें हाशिये पर धकेला जा रहा है या उनके लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है।

इसके साथ ही यह दुष्प्रचार भी उन्हें उन्माद और बदले की आग से भरता है कि उनकी मजहबी मान्यताएं या फिर मजहब ही खतरे में है। ऐसा दुष्प्रचार केवल कट्टरपंथी तत्व ही नहीं करते। वोट बैंक की सस्ती राजनीति के चलते दल विशेष के नेता भी ऐसा ही कुछ माहौल बनाते हैं। यह माहौल उन्माद से ग्रस्त हो रहे तत्वों के लिए विक्टिम कार्ड खेलने और कई बार आतंक के रास्ते पर चलने का जरिया बन जाता है।

Date: 14-11-25

भविष्य को आकार दे रही तकनीक

जसप्रीत बिंद्र, (लेखक एआइ एंड बियांड के संस्थापक हैं)

हाल में आए एक आंकड़े से पता चला कि चीन अमेरिका की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा बिजली उत्पन्न करता है और उसका लक्ष्य हर साल "एक जर्मनी" के बराबर बिजली उत्पादन जोड़ने का है। एलन मस्क का भी कहना है कि अगले तीन-चार वर्षों में चीन में सौर ऊर्जा का उत्पादन अमेरिका के सभी स्रोतों से संयुक्त रूप से अधिक होगा। वास्तव में भविष्य को आकार देने वाली तकनीक के युग में चार तकनीकें तय करेंगी कि कौन आगे रहेगा- ऊर्जा, गतिशीलता (मोबिलिटी), एआइ और युद्ध की रणनीति (वारफेयर)।

वर्ष 2010 से अब तक चीन का बिजली उत्पादन दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 10,000 टेरावाट-घंटा हो गया है, जबकि अमेरिका पिछले एक दशक से 4,000 टेरावाट-घंटा पर ठहरा हुआ है। असल बात यह है कि चीन सिर्फ बिजली की दौड़ नहीं जीत रहा, बल्कि वह यह स्वच्छ ऊर्जा के साथ कर रहा है। सिर्फ 2025 की पहली छमाही में चीन ने 212 गीगावाट सौर ऊर्जा जोड़ी, जो अमेरिका की कुल स्थापित क्षमता से भी अधिक है।

2024 में चीन ने 14.4 गीगावाट हाइड्रोपावर जोड़ी, जो कई देशों के कुल उत्पादन से अधिक है और 58.7 गीगावाट पंप्ड-स्टोरेज हाइड्रो तक पहुंच गया है एवं 200 गीगावाट से अधिक निर्माणाधीन है। वह परमाणु ऊर्जा में भी सक्रिय है, जहां 30 रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। कम वाणिज्यिक बिजली दरों और विशाल विनिर्माण की बदौलत बैटरी क्षेत्र में चीन ने फिर से ग्लोबल सप्लाई-चेन रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। सौर विनिर्माण की हर अवस्था में चीन की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है। ऊर्जा वह कच्चा माल है, जो बाकी सभी मूलभूत तकनीक को चलाएगा। चीन इसमें में काफी आगे निकल चुका है और उन कीमतों पर, जिनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता।

गतिशीलता में भी चीन आगे है। उसने इलेक्ट्रिक वाहनों पर वर्चस्व स्थापित कर लिया है। 2024 में चीन ने वैश्विक इलेक्ट्रिक कार बिक्री का लगभग दो-तिहाई हिस्सा अपने नाम किया। घरेलू बाजार में हर महीने बेची जाने वाली आधी कारें इलेक्ट्रिक हैं और दुनिया के शीर्ष 10 इलेक्ट्रिक वाहन के ब्रांडों में से छह अब चीनी हैं। चीन के वाहन अब उभरते बाजारों पर कब्जा कर रहे हैं। चीन में 100 से अधिक कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन बनाती हैं। एआइ के नए माडल बनाने में अब भी अमेरिका आगे है, लेकिन जब एआइ का फोकस "नवाचार" से "विस्तार" पर शिफ्ट हो रहा है, तो असली जीत सिर्फ माडल की बेंचमार्क से नहीं, बल्कि कंप्यूटर के लिए ऊर्जा, डाटा की उपलब्धता, नियामक गति और एप्लीकेशन अपनाने की दर से तय होगी।

अमेरिका के लिए आज की सबसे बड़ी बाधा है ऊर्जा। जहां अमेरिका ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है, चीन ने उस समस्या को पहले ही हल कर लिया है। स्वतंत्र आकलनों के अनुसार, 2030 तक चीन के डाटा सेंटर 400-600 टेरावाट-घंटा बिजली खपत करेंगे, जो तेजी से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से आएगी। अमेरिका का लक्ष्य 425 टेरावाट-घंटा डाटा सेंटर क्षमता स्थापित करने का है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि ऊर्जा कहां से आएगी। इसके अलावा, चीन एआइ पर आधारित रिसर्च पेपर और पेटेंट में अग्रणी है, जिसमें जेनरेटिव एआइ से जुड़े आवेदन भी शामिल हैं।

चीन एआइ के अगले बड़े चरण रोबोटिक्स में भी व्यापक बढ़त बनाए हुए है। 2023 तक चीन के पास दुनिया के कुल औद्योगिक रोबोट्स का 51 प्रतिशत हिस्सा था और वह हर साल लगभग 2.8 लाख नए रोबोट इंस्टाल कर रहा है। इसका लाभ उसे निर्यात प्रतिस्पर्धा, मजदूरी गतिशीलता और रक्षा औद्योगिक क्षमता में वृद्धि के रूप में मिलेगा। जल्द ही एआइ एक साफ्टवेयर इंटरफेस वाला ऊर्जा व्यवसाय बन जाएगा।

सच्चाई यह है कि जहां अमेरिका बेहतर माडल बनाने का जश्न मना रहा है, वहीं चीन ने यह सुलझा लिया है कि उन्हें वास्तव में चलाएगा कौन। पिछले कुछ वर्षों में युद्ध का स्वरूप भी बदल गया है। अब युद्ध सस्ते ड्रोन और घूमने वाले गोला-बारूद से लड़े जा रहे हैं, न कि महंगे टैंकों और विमानों से। ड्रोन निर्माण में चीन का वर्चस्व है। उसकी कंपनी डीडेआइ के पास वैश्विक ड्रोन बाजार का 70 प्रतिशत हिस्सा है। इसके मैविक ड्रोन के माडल 300 से 5,000 डालर के बीच आते हैं।

ड्रोन विशेषज्ञ बाबी सकाकी के अनुसार, "डीडेआइ हर साल लाखों ड्रोन बना सकता है, जो अमेरिका की तुलना में सौ गुना अधिक है।" अमेरिका सबसे उन्नत युद्ध ड्रोन बनाता है, लेकिन उनकी कीमत 6 से 13 मिलियन डालर तक होती है। युद्ध के सिद्धांत अब सस्ते ड्रोन, मानव रहित विमान की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें चीन उत्कृष्ट है। इसी बीच अमेरिका के एफ-35 कार्यक्रम की कुल लागत 1.58 ट्रिलियन डालर तक पहुंच गई है, जिससे भविष्य के रक्षा निवेशों के लिए जगह घट गई है।

वैश्विक स्तर पर बन रही इस स्थिति में प्रासंगिक बने रहने के लिए भारत को अपनी विकास रणनीति को तीन बातों पर केंद्रित करना चाहिए- बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन, अपने घरेलू बाजार से परे निर्यात बाजार की खोज और अग्रणी तकनीक तक पहुंच। इन तीनों में चीन का वर्चस्व है। भारत की "मल्टी-अलाइनमेंट" रणनीति समझदारी भरी है, लेकिन अब गणित कहता है कि थोड़ा झुकाव जरूरी है। जहां चीन के साथ गठबंधन भारत के हित में हो, वहां वह साझेदारी करे और बाकी मुद्दों को अलग रखे। इसका अर्थ चीन के अधीन होना नहीं है, बल्कि उन विशिष्ट मुद्दों पर सहयोग है, जो भारत की राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करें।

बिज़नेस स्टैंडर्ड

Date: 14-11-25

प्रगति को ऊर्जा या संसाधन का दोहन

मिहिर शाह, सुनील मणि, (लेखक क्रमशः शिव नादर विश्वविद्यालय में विशिष्ट प्रोफेसर तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, तिरुवनंतपुरम और अहमदाबाद विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर हैं)

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में डेटा सेंटर से जुड़े निवेश में असाधारण पैमाने पर बढ़ोतरी हो रही है और इस कारण देश, वैश्विक स्तर की दिग्गज तकनीकी कंपनियों के लिए एक अहम केंद्र बन रहा है। इसका उल्लेखनीय उदाहरण है गूगल की यह घोषणा कि वह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) डेटा हब में पांच वर्षों के दौरान 15 अरब डॉलर का निवेश करेगी। भारत के डेटा सेंटर क्षेत्र में अब कुल आईटी लोड (कंप्यूटिंग उपकरणों द्वारा खपत की गई कुल बिजली) 1.7 गीगावॉट से अधिक है और जिन डेटा सेंटर का विकास हो रहा है उनसे अतिरिक्त 2.5-3 गीगावॉट की खपत होगी।

एसटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स इंडिया 400 मेगावॉट की कुल 30 परियोजनाओं का प्रबंधन करती है जबकि योट्टा डेटा सर्विसेज 434 मेगावॉट क्षमता वाले तीन बड़े डेटा सेंटर साइट का संचालन करती है। एनटीटी कम्युनिकेशंस और कंट्रोलएस डेटासेंटर्स क्रमशः 268 मेगावॉट और 250 मेगावॉट का प्रबंधन करते हैं। सिफी टेक्नॉलजीज नेक्स्ट्रा डेटा और अदाणीकॉनेक्स जैसी भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियां 33 मेगावॉट से 200 मेगावॉट के बीच योगदान देती हैं।

हालांकि, इन निवेशों के बावजूद महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। भारत दुनिया के लगभग 20 फीसदी डेटा का उत्पादन करता है। लेकिन वैश्विक डेटा सेंटर क्षमता में इसका योगदान केवल 3 फीसदी है जिससे मांग-आपूर्ति का एक उल्लेखनीय अंतर पैदा होता है। इसने राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज कर दी है और प्रत्येक राज्य बड़े पैमाने के केंद्रों को आकर्षित करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन, भूमि अनुदान और नियामकीय फास्ट ट्रैक सुविधा की पेशकश कर रहे हैं। इसके आर्थिक लाभ स्पष्ट हैं। रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और प्रौद्योगिकी के प्रसार से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव आ रहा है।

डेटा सेंटर नीति, 2020 ने नियामक सुधारों और व्यावसायिक परिचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए ढांचा स्थापित किया जबकि हाइपरस्केल डेटा सेंटर योजना का लक्ष्य पांच वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपये तक निजी निवेश आकर्षित करना है जो सितंबर 2021 में 12,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शुरू की गई थी। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2022 ने डेटा और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया, जिससे परिचालकों को लंबी अवधि की कम लागत वाली फंडिंग तक पहुंच बनाने में मदद मिली और डेटा सेंटर को अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के साथ स्थान मिला।

राष्ट्रीय डेटा सेंटर नीति 2025 के मसौदे पर फिलहाल परामर्श जारी है और इसमें प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहनों का प्रस्ताव है। जिसमें क्षमता विस्तार, ऊर्जा दक्षता और रोजगार सृजन के लक्ष्यों को पूरा करने वाली फर्मों के लिए 20 साल तक की सशर्त कर छूट शामिल है। इसके अलावा अतिरिक्त उपायों में पूंजीगत परिसंपत्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का विस्तार करना और आसानी से मंजूरी देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस तंत्र शुरू करना शामिल है। सामूहिक रूप से,

इन पहलों का लक्ष्य उद्योग के अगले विकास चरण के लिए एक मजबूत, निवेशक - अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

हालांकि, इस विस्तार के पर्यावरणीय प्रभाव भी काफी हैं लेकिन इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। भौगोलिक रूप से, यह उद्योग पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर केंद्रित है और इसकी क्षमता में मुंबई का योगदान 41 फीसदी और चेन्नई का फीसदी है। गूगल की विशाखापत्तनम परियोजना से पूर्वी तट की क्षमता बढ़ने और क्षेत्रीय क्लाउड तथा एआई बुनियादी ढांचे के केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। लेकिन भारत के तटीय क्षेत्र, पारिस्थितिकी रूप से सबसे नाजुक क्षेत्रों में से हैं।

पानी के अत्यधिक उपयोग से तटों पर ताजे पानी में खारापन बढ़ने और बाद का खतरा बढ़ने जैसे जोखिम हो सकते हैं। भारत के तटीय इलाकों में भूजल स्तर काफी ऊपर है और पीने योग्य ताजे पानी की एक पतली ऊपरी परत ही है। ऐसे में इन नई सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पहलों के लिए भूजल का अधिक इस्तेमाल करने से खारे पानी के भूजल में घुसने का जोखिम बढ़ सकता है जिससे वह हमेशा के लिए दूषित हो सकता है। पानी का स्तर गिरने से जमीन भी धंस सकती है, जिससे ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं। ऐसे भूजल स्रोत बहुत संवेदनशील होते हैं और इन्हें बचाने, नुकसान कम करने और समुद्री पानी को रोकने के लिए खास ध्यान देना होगा।

इन संयंत्रों की पानी की जरूरतें बहुत ज्यादा होती हैं क्योंकि इनके कूलिंग तंत्र हर साल लाखों लीटर पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर इनकी स्थापना उन क्षेत्रों में हो रही है जहां पानी की कमी है, जैसे मुंबई और चेन्नई । कुछ परिचालक अब हवा से ठंडी करने वाली या क्लोज्ड लूप सिस्टम अपना रहे हैं, लेकिन ये विकल्प अब भी सीमित हैं। कई केंद्र अब भी पानी की बहुत खपत करने वाले वाष्पीकरण कूलिंग पर निर्भर हैं। डेटा केंद्र बड़ी मात्रा में बिजली की भी खपत करते हैं। वैश्विक अनुमान बताते हैं कि वर्ष 2030 तक, वे दुनिया की 8 फीसदी तक बिजली उपयोग कर सकते हैं। भारत में, इस क्षेत्र की बढ़ती बिजली की मांग ग्रिड पर अतिरिक्त दबाव डालती है। भारत का ग्रिड अब भी काफी हद तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है, जिससे कार्बन उत्सर्जन को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

दुनिया भर की समाचार रिपोर्ट (ब्राजील, ब्रिटेन, चिली, आयरलैंड, मलेशिया, मेक्सिको, नीदरलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और स्पेन से) यह दर्शाती हैं कि जैसे-जैसे तकनीकी कंपनियां एआई को आगे बढ़ाने के लिए डेटा सेंटर बना रही हैं, वैसे ही कमजोर समुदायों को बिजली कटौती और पानी की कमी का सामना करना पड़ा है। इन गैर-टिकाऊ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तरीकों को लगातार जारी रखने से रोकने के लिए, भारत को डेटा केंद्र विस्तार के हर चरण में पर्यावरणीय स्थिरता को शामिल करना होगा। इसका मतलब है कि अक्षय बिजली स्रोतों का उपयोग करना, ऊर्जा कुशल बुनियादी ढांचा अपनाना और साथ ही, अत्याधुनिक कूलिंग तथा पानी को रिसाइक्लिंग करने वाली प्रणालियां लागू करना जरूरी है।

सभी भारतीय उद्योगों की तरह, डेटा केंद्रों के निवेश के मामले में भी पानी के व्यापक उपयोग की ऑडिट को एक नियमित प्रक्रिया बनाना जरूरी है। सभी कंपनियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अपने वॉटर फुटप्रिंट का विवरण देना चाहिए, साथ ही उन कदमों का भी जिक्र करना चाहिए जो वे पानी की मांग कम करने के लिए उठा रहे हैं। ऐसा करने से उपयोग किए गए पानी की प्रति इकाई अधिक मूल्यवर्धन होगा। इसके साथ ही अलग-अलग प्रक्रियाओं में पानी के विशिष्ट उपयोग के लिए मानक विकसित किए जाने चाहिए। प्रत्येक उत्पाद के लेबल पर उसका वॉटर फुटप्रिंट दर्शाया

जाना चाहिए। प्रौद्योगिकियों और निवेशों के माध्यम से वॉटर फुटप्रिंट को काफी हद तक कम किया जा सकता है जिनका लाभ बहुत कम समय में मिलना शुरू हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के हेलसिंकी डेटा केंद्र जैसे अंतरराष्ट्रीय उदाहरण इसकी क्षमता दिखाते हैं। वहां बरबाद हो रही गर्मी की आपूर्ति पास के घरों में की जाती है और अक्षय ऊर्जा को प्राथमिकता दी जाती है, और नए एयर कूलिंग तरीके पानी के उपयोग को कम करते हैं।

डिजाइन और संचालन में टिकाऊपन को शामिल कर भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि डेटा संचालित उसकी यह वृद्धि आर्थिक और तकनीकी लक्ष्यों का समर्थन करे और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करे तथा कार्बन उत्सर्जन कम करे। हरित बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर, कुशल जल प्रबंधन और अक्षय ऊर्जा को अपनाकर, भारत खुद को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार डिजिटल विकास में एक वैश्विक अगुआ के रूप में स्थापित कर सकता है।

राष्ट्रीय सहारा

Date: 14-11-25

आरटीआई का दुरुपयोग कर रहे ब्लैकमेलर्स

संपादकीय

आम नागरिक सरकारी विभाग, पुलिस, न्यायधीश, सूचना आयोग. सब के सब ब्लैकमेलर्स अफवाह बाज शिकायती गिरोहों से परेशान है। सूचना आयुक्त और सरकारी विभागों ने साफ कहा है कि सूचना के अधिकार और मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल (आईजीआरएस) का खूब दुरुपयोग हो रहा है। इसी तरह आम समाज की ताकत सोशल मीडिया / एआई भी अफवाहबाजों का हथियार बन गई है। जनहित याचिकाओं के बेजा इस्तेमाल से न्याय व्यवस्था परेशान है। जिसके होते झूठी और फर्जी तथ्यहीन आरोपों पर बार-बार याचिकाएं दाखिल करने वालों को अर्थदंड का प्रावधान लागू किए जाने पर मजबूर होना पड़ा है सोशल मीडिया के साथ एआई (आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस) की आधुनिक तकनीक को अफवाह बाजों ने कोढ़ में खाज बना दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही एआई जनरेट तस्वीर ने सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैला दी कि लखनऊ के पॉश कॉलोनी में शेर धूम रहा है। ऐसी तस्वीर बनाकर वायरल करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लखनऊ पुलिस ने इस अफवाह पर विराम लगाया। इसी तरह एआई तकनीक से एक फर्जी वीडियो में दिखाया गया कि देश की प्रतिष्ठित महिला पत्रकार गृह मंत्री के जूते साफ कर रही है। अफवाह बाजी की ऐसी एक नहीं सैकड़ों-हजारों कहानियां है।

ब्लैकमेलर और अफवाह बाज सूचना का अधिकार कानून और सोशल मीडिया का खूब दुरूपयोग कर रहे है। एजेंडा धारी स्वार्थवश झूठे एजेंडे चला रहे है। साइबर अपराध खूब फल फूल रहा है। सूचना का अधिकार जनहित याचिका हो, आई जी आर एस या सोशल मीडिया आम नागरिकों के ये जायज हथियार नाजायज तरीके से हथिया लिया जा रहा है वैसे ही जैसे देश की हिफाजत करने वाले सैनिकों का हथियार आतंकवादियों के हाथ आ जाए। पिछले दो दशक में बहुत कुछ

बदला है। तकनीक का तेजी से विस्तार हुआ और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। सोशल मीडिया और सूचना का अधिकार का सदुपयोग भी हो रहा इसमें कोई शक नहीं, किंतु दुरुपयोग अधिक हो रहा ये अत्यंत चिंता का विषय है। जरूरत इस बात की है कि आम नागरिक अपनी ताकत की पहरेदारी करें, कानून, शासन-प्रशासन इन विसंगतियों पर सख्त हो । नागरिक सोशल मीडिया के झूठ और सच को समझें, जरूरत के लेहाज से इसका अधिक से अधिक सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग करें। नहीं तो खुले गुड़ पर मक्खियों की तरह शरीफ आमजन की ताकत को बदमाश ब्लैकमेलर, अफवाह बाज, समाज-विरोधी एजेंडा धारी दबंग हथियार ले रहे हैं।

सोशल मीडिया सूचनाओं, जानकारियों, ज्ञान, सकारात्मक कंटेट प्रतिभाओं, झूठ के खिलाफ सच्चाइयों को आसानी से परोसने और आगे बढ़ाने का बेहतरीन माध्यम है। सूचना का अधिकार सूचनाएं, जानकारियां प्राप्त करने, पादर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता का अधिकार है और ताकतवर हथियार भी। सोशल मीडिया के हथियारों के साथ जनहित याचिकाओं और शिकायत के अधिकारों का दुरपयोग करने वाले शिकायती गिरोहों को ब्लैकमेलिंग के धंधे जितना परवान चढ़ रहे हैं आम नागरिकों का अधिकार कमजोर पड़ रहा है। वे चिंता का विषय है और इसपर लगाम बेहद जरूरी है। ब्लैकमेलिंग के माफिया आम इंसानों की ताकत और अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर उनके अधिकारों को निरंतर कमजोर कर रहे है। आरटीआई की साइट पर जाइए और शिकायतों के विवरण पर गैर कीजिए तो पता चलेगा कि चंद नाम निरंतर दर्जनों सूचनाएं मांगे जा रहे है और ऐसा ही मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर भी कुछ शिकायतकर्ता या तो बार-बार शिकायत कर रहे हैं या फिर फर्जी नामों या डमी नामों से शिकायतें खूब की जा रही है। ऐसे ही ब्लैकमेलिंग के इरादे से शिकावती गिरोह का एक एक सदस्य आधा आधा दर्जन जनहित याचिकाएं दाखिल किए है और बाद में अधिकांश याचिकाओं की पैरवी बंद कर दी जाती है। यानि समझौता, सफल निगोशिएशन या यूं कहिए कि ब्लैकमेलिंग का ऑपरेशन लेन-देन सफल और याचिकाएं, शिकायते, सूचनाएं डंप या वापस ले ली जाती है।

राज्य सूचना आयुक्त और लखनऊ विकास प्राधिकरण सहित कई सरकारी विभागों के अनुसार एक व्यक्ति दर्जनों सैकड़ों बार सूचनाएं मांगता और शिकायतें करता है। ये लोग संगठित तौर पर पैरवी और अपील में भी डटे रहते है। ऐसे में आम इंसान की जायज शिकायत या मांगी गई सूचना धंधेबाजों की भीड़ में बहुत पीछे हो जाती है। खबर के लिए सूचनाएं मांगने और भष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार भी ब्लैकमेलरों के संगठित गिरोहों से परेशान है। ब्लैकमेलिंग, रंगदारी और वसूली के गिरोह आरटीआई और आईजीआरएस पर फर्जी नामों से भी शिकायतें करते है। इसके लिए इनके पास कुछ डमी कैंडीडेट्स की आईडी होती है। शिकायत में उमी नाम से करते है और पैरवी अपील और सूचना / शिकायत का प्रचार प्रसार खुद करते हैं ऐसे गैंग बाकायदा सिस्टेमैटिक ढंग से काम करते है। एक विंग के लोगों की आईडी या सिग्नेचर / फर्जी सिग्नेचर से सूचनाएं मांगी जाती है। आईजीआरएस की जाती है जनहित याचिकाएं मांगी जाती है। ये धमकी भरे नोटिस भेजने और धोखाधड़ी से फर्जी एफआईआर / 156 (3) कराने में भी माहिर होते है।

Live हिन्दुस्तान.com

Date: 14-11-25

खुलती साजिश

संपादकीय

लाल किला कार विस्फोट की जिस बड़े पैमाने पर जांच चल रही है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अव्वल तो अब सरकार ने मान लिया है कि यह आतंकी साजिश थी और इस साजिश को परत दर परत खोलने का सिलसिला भी आगे बढ़ चला है। कम शब्दों में कहें, तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सफेदपोश आतंक पर टूट पड़ी हैं। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कम से कम चार राज्यों में लगातार छापे पड़ रहे हैं और अनेक संदिग्धों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। एजेंसियों की सक्रियता यह साफ बता रही है कि सरकार बहुत गंभीर है। जल्दी से जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी करने का इरादा है। सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी चिंता यह है कि साजिश का कोई भी सिरा बाहर खुला न रह जाए। गुरुवार शाम तक साजिश में शामिल तीसरी कार भी मिल गई है। एजेंसियों को उस मुकाम तक पहुंचना होगा, जहां वे देश को आश्वस्त कर सकें। इतना तो तय है कि यह आतंकी साजिश बहुत बड़ी और भयानक थी । आशंका यह भी है कि विस्फोटों में लगभग 32 पुराने वाहनों का इस्तेमाल करने की साजिश थी।

जांच में एनआईए और फोरेंसिक टीम की सर्वाधिक भूमिका है। दोषियोंया आतंकियों की सही पहचान करना जरूरी है और इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कुशलता से हो रहा है। लोगों को आतंकियों की पूरी कड़ी पर शिकंजे का इंतजार है। कहना न होगा, सफेदपोश आतंक को काबू में करना इतना आसान नहीं है। एक पूरा विश्वविद्यालय संदेह के दायरे में आ गया है, उससे जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत कठिन है, लेकिन उन्हें इस दौर से सफलतापूर्वक गुज़रना होगा। एजेंसियों का पूरा साथ देना होगा, ताकि जल्द से जल्द जांच पूरी हो । अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों के अपराध की सजा अनेक लोग भुगतते हैं। यह एहसास समाज के एक बड़े हिस्से में है। मनभेदया मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन जब मामला आतंकवाद का आता है, तब शून्य सहिष्णुता के अलावा अन्य कोई मार्ग बचता नहीं है। देश और उसके नेताओं ने यह साफ संदेश दे दिया है कि देश अपनी धरती पर किसी भी प्रकार के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह भी प्रशंसनीय है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी सहित प्रमुख भारतीय मुस्लिमों ने हालिया बम विस्फोट की कड़ी निंदा करते हुए इसे राष्ट्र और हर भारतीय की साझा विरासत पर हमला बताया है । यह संदेश देना बहुत जरूरी है कि पूरा भारतीय समाज आतंक के खिलाफ एकजुट है।

आतंकवादी क्या चाहते थे या क्या चाहते हैं, इसे समझना जरूरी है। अगर उनकी साजिश फिर दिल्ली व अन्य शहरों को दहलाने की है, तो उन्हें किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहिए। तेजी से विकास की सीढ़ियां चढ़ता भारत आतंकवाद को नहीं झेल सकता। हम नक्सलवाद का अंत करने जा रहे हैं, तो आतंकवादका भी अंत करना है। डेढ़ दशक से भी ज्यादा समय से दिल्ली में विस्फोटनहीं हुआ था, इससे पता चलता है कि सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों पर अंकुश रखने में सक्षम हैं। आतंकियों की अगर नई खेप आई है, उसका फन कुचलकर ही दम लेना चाहिए। एक बड़ी चिंता कश्मीर में दिख रहे सफेदपोश आतंक को लेकर है। पढ़े-लिखे युवाओं को पथभ्रष्ट होने से बचाना होगा। जो देशद्रोही लोग या संगठन युवाओं को बरगलाने में लगे हैं, उनका अंत सबसे पहले होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि जांच में किसी निर्दोष को न सताया जाए और किसी दोषी के प्रति कोई सहानुभूति न बरती जाए।